मुख्य न्यायमूर्ति बिनोद कुमार रॉय, न्यायमूर्ति एन.के. सूद एवं न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता के समक्ष,

स्विफ्ट फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड &

अन्य,-हस्तांतरणकर्ता कंपनियाँ

बनाम

इंडस्ट्रीज़ स्विफ्ट लिमिटेड, - ट्रांसफ़री कंपनी कंपनी

याचिका संख्या 138 ऑफ़ 2003

31 मार्च, 2004

कंपनी अधिनियम, 1956—धारा 391(2)-कंपनियों के एकीकरण की योजना को मंजूरी देना- धारा 391(2) में प्रावधान है कि बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों/शेयरधारकों के 3/4वें मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत को इस व्यवस्था पर सहमत होना होगा - चाहे बहुमत कुल लेनदारों/शेयरधारकों के मूल्य के 3/4वें का प्रतिनिधित्व करता हो या बैठक में वास्तव में उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों/शेयरधारकों का मूल्य-व्याख्या-धारा 391(2) के तहत 3/4 के बहुमत की आवश्यकता को उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शेयरों/क्रेडिट के मूल्य के संबंध में देखा जाना चाहिए। बैठक में या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा - इसका मतलब यह नहीं है कि 3/4 बहुमत कंपनी के ऋणदाताओं/शेयरधारकों के कुल मूल्य का होना चाहिए।

(यूरो कॉटस्पिन लिमिटेड के मामले सीपी संख्या 324/2002 पर 11 जुलाई, 2003 को फैसला सुनाया गया, खारिज कर दिया गया)

निर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 391(2) के प्रयोजनों के लिए, तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता को बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शेयरों/क्रेडिट के मूल्य के संबंध में देखा जाना चाहिए, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा। इस प्रावधान की यह व्याख्या नहीं की जा सकती कि तीन-चौथाई बहुमत कंपनी के लेनदारों/शेयरधारकों के कुल मूल्य का होना चाहिए। यह सही ढंग से इंगित किया गया है कि बाद का दृष्टिकोण अपनाने से "वर्तमान और मतदान" शब्द निरर्थक हो जाएंगे, जो निर्माण के सुस्थापित नियमों के विपरीत होगा। यदि इरादा कुल मूल्य का तीन-चौथाई बहुमत रखने का था, तो प्रावधानों को तदनुसार लिखा जाता। अधिनियम की धारा 391(2) की भाषा पूरी तरह से स्पष्ट है और इस प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिस बहुमत से किसी समझौते या व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, उसे लेनदारों/शेयरधारकों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। 'वर्तमान और मतदान' न कंपनी के शेयरधारकों या लेनदारों का है बल्कि 'कुल' मूल्य का है।

(पैरा 13)

2003 के सीपी 203 में अनिल बी. दीवान और एल.एम. सूरी, वरिष्ठ वकील, दीपक सूरी और सुमीत गोयल, वरिषठ वकीलों के साथ।

2003 के सीपी 8 में आर.एस. अरोड़ा, वकील।

2003 के सीपी 138 में अमित सिंह, वकील।

2003 के सीपी 150 में सुमीत गोयल, वकील।

याचिकाकर्ताओं के लिए 2003 के सीपी 223 में अक्षय भान, वकील।

एम.एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में सुश्री जयश्री ठाकुर, अधिवक्ता, न्याय मित्र।

निर्णय

न्यायमूर्ति एन.के. सूद,

(1) इस संदर्भ में, हमें कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 391 की उपधारा (2) की व्याख्या करने और इसका सही अर्थ और आयात निर्धारित करने के लिए कहा जाता है।

(2) यह प्रावधान इस प्रकार है:-

"(2) यदि लेनदारों, या लेनदारों के वर्ग, या सदस्यों, या सदस्यों के वर्ग के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या में बहुमत, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और मतदान करें, या जहां प्रॉक्सी की अनुमति है धारा 643 के तहत बनाए गए नियमों के तहत, बैठक में प्रॉक्सी द्वारा, किसी भी समझौते या व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की जाती है, समझौता या व्यवस्था, यदि न्यायालय द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो सभी लेनदारों, वर्ग के सभी लेनदारों, सभी पर बाध्यकारी होगी। सदस्यों या वर्ग के सभी सदस्यों पर, जैसा भी मामला हो, और कंपनी पर भी, या किसी कंपनी के मामले में, जिसे बंद किया जा रहा है, कंपनी के परिसमापक और योगदानकर्ताओं पर।"

(3) 2003 की कंपनी याचिका संख्या 138 में कंपनियों के एकीकरण की योजना को मंजूरी देने के लिए अधिनियम की धारा 391(2) और 394 के तहत एक याचिका है; अर्थात्, स्विफ्ट फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड और मुकुर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक अन्य कंपनी के साथ: अर्थात्, इंड-स्विफ्ट लिमिटेड।

(4) अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों/शेयरधारकों के तीन-चौथाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत को इस व्यवस्था से सहमत होना होगा। इस मामले में, हस्तांतरित कंपनी के असुरक्षित लेनदारों/शेयरधारकों की बैठकें 22 अप्रैल, 2003 को आयोजित की गईं। असुरक्षित लेनदारों की बैठक में रुपये के मूल्य के क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 लेनदारों ने भाग लिया। 15,48,77,556/-. इस कंपनी के असुरक्षित लेनदारों का कुल मूल्य रु. 27,19,01,000/-। इस व्यवस्था को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसी प्रकार, शेयरधारकों की बैठक में 38 शेयरधारक रुपये के मूल्य के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैठक में 1,25,17,560/- उपस्थित थे। 37 शेयरधारकों ने व्यवस्था के अनुमोदन के लिए मतदान किया, जबकि एक शेयरधारक के पास रुपये के मूल्य के 100 शेयर थे 1,000/- ने इसके विरोध में वोट किया। हालाँकि, इस कंपनी की जारी और सब्सक्राइब की गई शेयर पूंजी का कुल मूल्य रु 4,39,50,000/- है।

(5) जब याचिका कंपनी न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए आई तो यह सवाल उठा कि क्या अधिनियम की धारा 391 की उपधारा (2) में निर्धारित अपेक्षित बहुमत से व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी या नहीं? याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि व्यवस्था को संबंधित बैठकों में उपस्थित

और मतदान करने वाले लेनदारों/शेयरधारकों के तीन-चौथाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 391 की उपधारा (2) की आवश्यकता है पूरा हुआ. अपने दावे के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने **हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड**[1] के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया था जिसमें यह माना गया है कि "इस धारा के निर्माताओं का इरादा यह था कि तीन-चौथाई मूल्य का बहुमत उन व्यक्तियों का होना चाहिए, जो उपस्थित थे और जिन्होंने मतदान में भाग लिया था।" हालाँकि, कंपनी जज ने देखा कि यूरो कॉटस्पिन लिमिटेड के मामले में 2002 के सीपी नंबर 324 में, 11 जुलाई, 2003 को निर्णय लिया गया था, यह माना गया था कि धारा 391 की उप-धारा (2) में तीन-चौथाई बहुमत की परिकल्पना की गई है। अधिनियम लेनदारों/शेयरधारकों के कुल मूल्य का होना चाहिए, न कि केवल बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों/शेयरधारकों के मूल्य का। चूंकि कंपनी न्यायाधीश ने यूरो कॉटस्पिन लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की सत्यता के बारे में अपने संदेह पर विचार किया था।

इस विचार से कि निम्नलिखित प्रश्न के समाधान के लिए इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है:-

> "क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 की उप-धारा (2) में परिकल्पित संख्या में बहुमत कुल लेनदारों/शेयरधारकों के मूल्य का तीन-चौथाई या वास्तव में मौजूद लेनदारों/शेयरधारकों के मूल्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और बैठक में मतदान?"
>
> (6) चूंकि 2003 के सीपी नंबर 8, 150, 203 और 223 में भी यही प्रश्न शामिल था, इसलिए इसे भी 2003 के सीपी 138 के साथ सुनने का आदेश दिया गया था।
>
> (7) इस प्रकार यह मामला अब हमारे सामने रखा गया है।

(8) याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल बी. दीवान द्वारा निम्नलिखित मुख्य दलीलें दी गईं:-

> (i) आमतौर पर कंपनियों की बैठकों में निर्णय ऐसी बैठकों में भाग लेने वाले लोगों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन जब कोई कंपनी कोई समझौता या व्यवस्था करने का प्रस्ताव करती है, जिससे सभी लेनदारों/शेयरों के हित प्रभावित होने की संभावना होती है- धारकों, उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 391 की उपधारा (2) के अनुसार इस तरह के समझौते या व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए बड़े बहुमत की आवश्यकता होती है।
>
> (ii) इस प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किसी व्यवस्था के लिए निम्नलिखित तरीके से बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है: -
>
> (ए) इसे उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या, जहां प्रॉक्सी की अनुमति है, प्रॉक्सी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए;

1

(बी) संख्या में उपरोक्त बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों/शेयरधारकों के मूल्य में तीन-चौथाई का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

उपरोक्त प्रावधान कहीं भी यह प्रावधान नहीं करता है कि बहुमत की संख्या लेनदारों/शेयरधारकों के "कुल मूल्य" के तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि ऐसी व्याख्या की जाती तो "उपस्थित होना और मतदान करना" शब्द निरर्थक हो जाते।

(iii) पुराने भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) के अनुरूप प्रावधान धारा 153 की उप-धारा (2) थी, जो इस प्रकार है: -

"(2) यदि लेनदारों या लेनदारों के वर्ग, या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुमत की संख्या, जैसा भी मामला हो, बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, तो किसी भी समझौते पर सहमत हों या व्यवस्था, समझौता या व्यवस्था, यदि न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो, सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग, या सभी सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, और कंपनी पर भी बाध्यकारी होगा, या किसी कंपनी के बंद होने की स्थिति में, कंपनी के परिसमापक और योगदानकर्ताओं पर।"

उपरोक्त प्रावधान में परिकल्पित बहुमत उन लेनदारों/शेयरधारकों के संबंध में था जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा बैठक में उपस्थित होते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि ऐसे व्यक्ति भी वास्तव में मतदान कर रहे हों। इस प्रावधान के तहत आधार अधिनियम की धारा 391 की उपधारा (2) में दिए गए आधार से कहीं अधिक व्यापक था, जिसके लिए सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है जो न केवल व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होते हैं, बल्कि जो अपने अधिकार का प्रयोग भी करते हैं। मत देने का अधिकार। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 391(2) में, जो व्यक्ति बैठक में उपस्थित होते हैं लेकिन मतदान नहीं करते हैं उन्हें विचार से बाहर रखा जाता है।

(iv) अंग्रेजी कानून के तहत संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1948 की धारा 206 की उप-धारा (2), जो समान शब्दों में है, इस प्रकार है: -

"(2) यदि लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग के मूल्य में तीन चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुमत की संख्या, जैसा भी मामला हो, बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित और मतदान करती है, तो किसी के लिए सहमत हों समझौता या व्यवस्था, समझौता या व्यवस्था, यदि न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो, तो सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग, या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, और कंपनी पर भी बाध्यकारी होगी। कंपनी के परिसमापक और योगदानकर्ताओं पर घाव होने की प्रक्रिया।

'बकले ऑन कंपनीज़ एक्ट' के तेरहवें संस्करण में, यह देखा गया है कि उपरोक्त प्रावधान के प्रयोजनों के लिए "व्यक्तिगत रूप से उपस्थित और मतदान करने वाले वर्ग के सदस्यों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या में बहुमत की मंजूरी या प्रॉक्सी द्वारा पर्याप्त है, हालांकि यह मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, न ही, कुल वर्ग की संख्या में बहुमत का गठन कर सकता है।

अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) के प्रावधान अंग्रेजी कानून के तहत उपरोक्त प्रावधान के बराबर हैं और इस प्रकार, तीन-चौथाई मूल्य निर्धारित करने का आधार शेयरों/क्रेडिट का मूल्य होना चाहिए बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा, न कि कंपनी के शेयरों/क्रेडिट का कुल मूल्य।

(v) कंपनी अधिनियम, 1948 को कंपनी अधिनियम, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जिसमें धारा 425 की उपधारा (2) में एक समान प्रावधान किया गया था, जो इस प्रकार है: -

"(2) यदि लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग (जैसा भी मामला हो) के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत, बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित और मतदान करते हैं, तो सहमत होते हैं किसी भी समझौते या व्यवस्था के लिए, समझौता या व्यवस्था, यदि न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो, सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग (जैसा भी मामला हो) पर और कंपनी पर भी बाध्यकारी है, किसी कंपनी के बंद होने की स्थिति में कंपनी के परिसमापक और योगदानकर्ताओं पर।"

इस प्रस्ताव में फिर से, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत स्टॉक/क्रेडिट के मूल्य के संबंध में तीन-चौथाई मूल्य की गणना करना आवश्यक है।

(vi) प्रोफेसर रॉबर्ट आर. पेनिंगटन (5वें संस्करण) अंग्रेजी कंपनी लॉ द्वारा, पृष्ठ 590 पर, 'वर्तमान और मतदान' शब्दों के उपयोग को दिखाया गया है

"...ऐसा ही कुछ होता है कि वोट भी दे सकते हैं और लेनदारों या मंडल की सामान्य बैठकों में और किसी भी सार्वजनिक कंपनी की सामान्य बैठकों में मंडल के सदस्यों की सहमति की अक्षमता व्यवस्था की मंजूरी के लिए मंजूरी दी गई बैठकों पर लागू नहीं होती है। प्रत्येक बैठक में योजना पर वोट एक सर्वेक्षण द्वारा लिया जाता है, और योजना को अनुमोदित प्रस्ताव के लिए लिया जाता है, वे व्यक्ति जो बैठक में व्यक्तिगत रूप से या समूह द्वारा शामिल होते हैं और जो योजना के पक्ष में मतदान करते हैं। व्यक्तिगत रूप से या मजबूती से और मतदान करने वाले सभी लोगों की संख्या को बहुमत में शामिल किया जाना चाहिए, <u>उन्हें ऐसे सभी लोगों के हितों का तीन-चौथाई मूल्य भी रखना चाहिए। जो व्यक्ति बैठक में शामिल होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, या जो बैठक में भाग लेते हैं लेकिन मतदान से दूर रहते हैं, उनकी संख्या और हितों का महत्व महत्वपूर्ण होता है, और गणना में बिल्कुल भी शामिल नहीं होते हैं।</u> इसी तरह, संवैधानिक नियुक्त करने वाले लोग हितों की अनदेखी करते हैं, यदि संवैधानिक बैठक में भाग नहीं लेते हैं, या भाग लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं..... .."

(जोर दिया)

.

(vii) इस प्रॉजेक्ट को पामर कंपनी लॉ के चौबीसवें संस्करण (पृष्ठ 1145 पर) में दिखाया गया है: -

"2. वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

न्यायालय को इस बात से सहमत होना चाहिए कि जो लोग बैठक में शामिल हुए थे, वे उस वर्ग के काफी प्रतिनिधि चाहते हैं और वैधानिक बहुमत ने उस वर्ग के विरोधाभासी हितों को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यकों के साथ जोर नहीं दिया, ताकि वे प्रतिनिधित्व कर सकें। ।।

यह आवश्यकता आंशिक रूप से पहली की एक उपज है। बहुमत के संबंध में, दो आवश्यकताएं हैं: योजना के पक्ष में मतदान करने वाले बहुमत को पहले वर्ग के एक सदस्य (चाहे लेनओन या ईसाई में) का बहुमत होना चाहिए जो इसमें शामिल हों और मतदान कर रहे हों और दूसरी बात हो, यह होना चाहिए ।। ऐसे लोगों की संपत्ति का मूल्य तीन-चौथाई हो।

इस प्रकार, यदि 100 सदस्य वोट कर रहे हैं (एक चरम उदाहरण लेने के लिए) एक सदस्य के पास 901 शेयर हैं और शेष के पास एक-एक शेयर हैं, तो एक-एक शेयर बनाए रखने वाले 99 शेयरधारक 901 शेयरधारक के वोट इसके विरुद्ध किसी भी योजना को लागू नहीं किया जा सकता है। , क्योंकि इनकी कीमत तीन चौथाई के करीब नहीं है। इसके विपरीत, शेयरधारक और 49 अन्य शेष 50 के खिलाफ किसी भी योजना को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि संख्या में बहुमत नहीं होगा। यही सिद्धांत लेनडोन पर भी लागू होता है।

इसमें देखा गया कि बहुसंख्यक वोट नेताओं का है, वोट देने वाले नामित लोगों का नहीं और न ही मौजूद लोगों का। इस प्रकार, जो शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या कमीशन द्वारा उपस्थित नहीं होते हैं, या जो उपस्थित होते हैं वे भी मतदान नहीं करते हैं, उन्हें नामांकित किया जा सकता है।

हालाँकि, यह पूरी तरह से आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके अलावा अदालत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वर्ग का प्रतिनिधित्व किया जाए। यदि, उदाहरण के लिए, वहाँ पूरी तरह से थे। कुल मिलाकर 10,000 शेयर रखने वाले 1,000 लोगों के लिए, अदालत की उस बैठक में वैधानिक बहुमत से चुनाव होने की संभावना नहीं थी, जिसमें कुल मिलाकर 100 शेयर रखने वाले 10 शामिल थे और मतदान किया गया था।'' (जोर दिया)।

(viii) गोवर के आधुनिक संस्करण में कंपनी कानून के सिद्धांत (छठे) में (पृष्ठ-585 पर) "लेनदार या लेनदार के वर्ग या सदस्य या वर्ग के मूल्य में तीन क्वार्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या में बहुमत" की अवधारणा और अर्थ सदस्य, जैसा मामला हो। उपस्थित होना और मतदान करना'' को निम्नानुसार एक उदाहरण देकर समझाया गया है:-

> “एक सामान्य परिणाम मतदान करने वालों के लिए सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, और इसका उपयोग सभी मामलों में अधिनियम या धारा के तहत किसी अन्य प्रकार के समाधान की आवश्यकता के लिए नहीं किया जाता है। तीन-चौथाई बहुमत से एक असाधारण प्रस्ताव पारित हो गया है लेकिन नोटिस की किसी विशेष अवधि की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम के तहत मौलिक समाधान की आवश्यकता केवल कुछ मामलों को समाप्त करने के लिए होती है, या जब कक्षा की बैठकों में वर्ग के अधिकार में संशोधन के लिए सहमति व्यक्त की जाती है। तीन-चौथाई बहुमत की ओर से भी एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन जिस बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया है, उसके लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन से पहले एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता है: और 1980 के दशक में कानून के ऐसे मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। विशेष और विशेष दोनों चट्टानों के

मामले में, बैठक के नोटिस में प्रस्ताव को अलग या विशेष प्रस्ताव, जैसा भी मामला हो, के रूप में प्रस्तावित करने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

इन तीनों मामलों में अपेक्षित बहुमत वोट देने के हकदार सदस्यों का है और वास्तव में या तो व्यक्तिगत रूप से या बीवी प्रॉक्सी द्वारा मतदान करते हैं जहां प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति है। यह माव और एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में सामान्य रूप से होगा। कुल सदस्यता के बहुमत से बहुत कम हो. और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से भी कम हो सकता है, क्योंकि जो लोग मतदान से बचते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक चरम मामले को लेने के लिए: वोटिंग अधिकार के बिना 500,000 वरीयता शेयरों और एक वोट के साथ 500,000 साधारण शेयरों वाली कंपनी की बैठक में केवल पांच सामान्य शेयरधारक शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक-एक शेयर होता है और एक के पास सौ शेयर होते हैं। यदि किसी मतदान में एक शेयर के तीन धारकों द्वारा किसी प्रस्ताव के पक्ष में और एक शेयर वाले चौथे शेयरधारक द्वारा विपक्ष में मतदान किया जाता है, सौ शेयरों के धारक ने मतदान नहीं किया है, तो समाधान विधिवत पारित हो चुका होगा, भले ही वह असाधारण या विशेष हो। संकल्प इसके बावजूद कि कुल दस लाख वोटों में से केवल तीन, कुल 500,000 वोटों में से तीन और बैठक में प्रयोग किए जाने वाले 104 वोटों में से केवल तीन ही वास्तव में इसके पक्ष में मतदान हुए हैं। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, हाथ उठाकर मतदान करने की प्रक्रिया, जब तक कि प्रभावी ढंग से मतदान की मांग न की जाए, और भी बड़ी विसंगतियाँ पैदा कर सकती है।

(जोर दिया गया)।

(ix) **रे बेसेमर स्टील एंड ऑर्डिनेंस कंपनी**[2] में जिसमें अंग्रेजी कानून के समान प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की गई है: -

"एकमात्र सवाल यह है कि क्या समझौते को अधिनियम द्वारा आवश्यक उचित संख्या में लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया गया है। अधिनियम की दूसरी धारा में प्रावधान किया गया है कि कंपनी के लेनदारों की बैठक समझौते को मंजूरी दे सकती है: - "यदि ऐसे लेनदारों या लेनदारों के वर्ग के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या में बहुमत, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो ऐसी बैठक, व्यवस्था या समझौते के लिए सहमत होगी, और समझौता या समझौता, यदि न्यायालय के आदेश द्वारा स्वीकृत हो, तो ऐसे सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग (जैसा भी मामला हो), और परिसमापक पर भी बाध्यकारी होगा और कंपनी के योगदानकर्ता।" इसलिए, सवाल यह है कि क्या "मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुमत" सभी लेनदारों का बहुमत होना चाहिए, इस मामले में 120.002 12s। 3डी. 170,000 का तीन-चौथाई नहीं बनता है। या बैठक में उपस्थित लेनदारों के उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुमत? बाद के मामले में, एक को छोड़कर सभी लेनदारों ने, बहुत छोटी राशि के लिए, समझौते को मंजूरी दे दी।

हम जानते हैं कि अधिनियम में खंड बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के मूल्य में तीन-चौथाई की मंजूरी से संतुष्ट है, और यह ट्यूनिस रेलवे कंपनी (22 मई, 1874) में आपके आधिपत्य

[2] जे. चांसरी प्रभाग 251

द्वारा तय किया गया था, अपील पर पुष्टि की गई (लॉर्ड्स जस्टिस के समक्ष, 11 जुलाई, 1874)।

डिक्सन की ओर से कार्सन ने कहा कि वह चाहते हैं कि व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए।

मालिन्स, वी.सी. .—

मेरा मानना है कि समझौते को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। कंपनी के सभी लेनदारों को इस बैठक की सूचना मिल गई, और यह माना जाना चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए, उन्होंने इसे उन लोगों पर छोड़ दिया जिन्होंने यह तय किया कि समझौता लाभप्रद था या नहीं, या उन्होंने इस मामले में इतनी कम दिलचस्पी ली कि उन्होंने उन्होंने इसमें शामिल होना उचित नहीं समझा। सभी घटनाओं पर। मुझे लगता है कि संसद के अधिनियम के तहत केवल उन्हीं लेनदारों की बात सुनी जानी चाहिए जो बैठक में उपस्थित थे। और यह कि उपस्थित लोगों का तीन-चौथाई मूल्य अनुबंध को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त है। (जोर दिया गया)।

(x) कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष **किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड**[3] में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या प्रस्तावित व्यवस्था को धारा के अर्थ के भीतर सुरक्षित लेनदारों की बैठक में अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया था। अधिनियम की धारा 391(2)। इस बैठक में 18 सुरक्षित लेनदारों ने भाग लिया और उनके ऋण का कुल मूल्य रु। 2,53,36,43,491. उपस्थित 18 में से एक ने मतदान में भाग नहीं लिया और उसके ऋण का मूल्य रु. 30,98,21,941. यह, उपस्थित और मतदान करने वाले सुरक्षित लेनदारों का कुल मूल्य रु। 2,22,38,21,550. रुपये के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दो वोट। 38,98,62,275 अवैध पाए गए। इसलिए, योजना को 15 लेनदारों के वोट द्वारा अनुमोदित किया गया था और उनके ऋण का मूल्य रुपये था। 1,83,39,59,275. जहां तक बहुमत की बात है तो कोई कठिनाई नहीं थी क्योंकि 15 लेनदारों ने योजना के पक्ष में मतदान किया था। हालाँकि, सवाल यह था कि क्या वे उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों के तीन-चौथाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक तीन-चौथाई बहुमत उन सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व मूल्य का था जो न केवल उपस्थित थे बल्कि जिन्होंने मतदान भी किया था। वास्तव में, यह एक कदम आगे बढ़कर यह मान लिया गया कि जो ऋणदाता उपस्थित थे और उन्होंने मतदान भी किया था, लेकिन जिनके वोट अवैध पाए गए थे, उन्हें नहीं हटाया जा सकता। कहा कि वोट दिया है क्योंकि अवैध वोट डालना कानून की नजर में वोटिंग नहीं है। इस प्रकार, यह माना गया कि "किसी भी प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा अनुमोदित या पारित किया गया है या नहीं, इसकी गणना करने में उचित निर्माण का मतलब वैध वोटों का मूल्य और उसी से बाहर है कि क्या प्रस्ताव पारित

[3] 2003 (116) कंपनी मामले 413

किया गया है तीन-चौथाई बहुमत के साथ" विद्वान वकील ने बताया कि व्यवस्था के पक्ष में वोटों का मूल्य रुपये था। 1,83,39,59,275, जो रुपये का तीन-चौथाई नहीं था। 2,53,36,43,491, यानी बैठक में उपस्थित 18 लेनदारों द्वारा दर्शाया गया मूल्य। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गणना के लिए आधार मूल्य केवल उन लेनदारों के संबंध में था जो न केवल उपस्थित थे बल्कि जिन्होंने वैध वोट डाला था।

(xi) **वसंत इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर, कोलाबा लैंड एंड मिल कंपनी लिमिटेड**[4], मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष, शेयरधारकों की एक बैठक में इस योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी, जहां 95 शेयरधारकों की कुल संख्या 30,675 थी। कुल 49,000 शेयरों में से शेयर मौजूद थे। इस प्रकार, इन 95 शेयरधारकों ने कंपनी के लगभग 62% शेयरों का प्रतिनिधित्व किया। आधिकारिक परिसमापक का यह तर्क कि चूंकि बैठक में उपस्थित शेयरधारकों ने केवल 62% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व किया था, यह आवश्यक था और न्याय के हित में कि बाकी शेयरधारकों के विचारों को भी सुनिश्चित किया जाए, न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। आधार यह है कि एक बार जब किसी योजना को अधिनियम की धारा 391 के तहत अपेक्षित बहुमत से मंजूरी मिल जाती है, तो यह कंपनी के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी हो जाती है। इस मुद्दे से निपटते हुए, न्यायालय ने रिपोर्ट के पृष्ठ-29 पर निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"इसलिए, यदि धारा 391 के तहत किसी योजना पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक में, योजना अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाती है, तो यह कंपनी के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी हो जाती है, चाहे इस सवाल पर ध्यान दिए बिना कि उन्होंने इसके लिए स्पष्ट रूप से सहमति दी है या नहीं नहीं। इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 391 के तहत, अदालत के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं हैक्या किसी कंपनी के सभी सदस्यों ने योजना के लिए स्पष्ट रूप से सहमति दी है, धारा के तहत, एक बार जब योजना अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाती है, तो सभी सदस्य इससे बाध्य हो जाते हैं। इस संबंध में, [1970] 3 ऑल ईआर 397 (सीएच डी) में रिपोर्ट की गई इन री ट्रिक्स लिमिटेड का संदर्भ लिया जा सकता है, जो अंग्रेजी कंपनी अधिनियम की धारा 245 के तहत समापन पर रोक के बीच स्पष्ट अंतर करता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 466 के समतुल्य) और अंग्रेजी अधिनियम की धारा 206 (भारतीय अधिनियम की धारा 391 के समतुल्य) के तहत बनाई गई व्यवस्था की एक योजना के तहत रोक। जबकि पूर्व में सभी शेयर धारकों की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है, बाद में शेयर धारकों और लेनदारों की एक बैठक का प्रावधान होता है जिसके लिए निर्धारित बहुमत से योजना को मंजूरी देना आवश्यक होता है। ऐसी मंजूरी पर योजना सभी शेयर धारकों या लेनदारों, जैसा भी मामला हो, के लिए बाध्यकारी हो जाती है। एस.के. के मामले में गुप्ता बनाम के.पी. जैन ने [1979] 49 कॉम्प कैस 342, पृष्ठ पर रिपोर्ट की। 350, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

[4] (1981) 51 कंपनी मामले 21

धारा 391 में कंपनी और कंपनी के सदस्यों और/या सदस्यों द्वारा विचार के लिए प्रस्तावित एक समझौते या व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जैसा भी मामला हो। कंपनी के लिए यह हमेशा खुला था कि वह किसी भी लेनदार को समझौते की पेशकश करे या प्रत्येक सदस्य के साथ समझौता करे। इस मामले में यह योजना मूलतः कंपनी और उसके असुरक्षित ऋणदाताओं के बीच एक समझौता है। स्वीकृत होने पर योजना केवल पार्टियों के बीच एक समझौते के रूप में काम नहीं करती है बल्कि इसमें वैधानिक बल होता है और यह न केवल कंपनी पर बल्कि असहमत लेनदारों या सदस्यों पर भी बाध्यकारी होती है, जैसा भी मामला हो। स्वीकृत योजना का प्रभाव उस प्रक्रिया का सहारा लेकर आपूर्ति करना है जिससे योजना से बंधे वर्ग के प्रत्येक सदस्य द्वारा उस व्यक्तिगत समझौते की अनुपस्थिति निर्धारित की जाती है जो अन्यथा इसे देना आवश्यक होगा वैधता (देखें जे.के. (बॉम्बे) पी. लिमिटेड बनाम न्यू कैसर-आई-हिंद एसपीजी. एंड डब्ल्यूवीजी. कंपनी लिमिटेड [1969] 2 एससीआर 866, 891; [1970] 40 कॉम्प कैस 689 (एससी)"।"

(xii) इस मामले के तथ्यों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 391 (2) के तहत परिकल्पित तीन-चौथाई बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों के मूल्य का होना चाहिए, न कि लेनदारों के स्थानीय मूल्य का।

मद्रास उच्च न्यायालय पुनः **नॉड्स वर्ल्डवाइड लिमिटेड**[5]जहां, इस व्यवस्था को एक बैठक में अनुमोदित किया गया था जिसमें कुल 300 शेयरधारकों में से 66 ने भाग लिया था, जिन्होंने हस्तांतरित कंपनी की भुगतान की गई पूंजी का 46.21% का प्रतिनिधित्व किया था, यह माना गया था कि अधिनियम की धारा 391 की आवश्यकता कायम है के साथ अनुपालन। पृष्ठ 896 पर इसे इस प्रकार देखा गया है:-

''.....जो लोग बैठक में शामिल हुए, उन्होंने 46.21 को नियंत्रित किया।अंतरिती कंपनी की चुकता पूंजी का प्रतिशत और योजना के अनुमोदन में लगभग एकमत थे। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 की आवश्यकता, संख्या में बहुमत की आवश्यकता और बैठक में भाग लेने वाले लोगों द्वारा रखे गए शेयरों के मूल्य का 75 प्रतिशत की आवश्यकता के संबंध में, संतुष्ट हो गई है... ....."

(xiii) अधिनियम की धारा 391 (2) के तहत बहुमत की आवश्यकता को शेयरों/क्रेडिट के कुल मूल्य के तीन-चौथाई बहुमत के रूप में व्याख्या करने से न केवल "वर्तमान और मतदान" की अभिव्यक्ति निरर्थक हो जाएगी, बल्कि प्रावधान भी हो जाएगा। पूर्णतः अव्यवहारिक एवं अव्यावहारिक। आज के कॉरपोरेट जगत में हमारे देश में बड़ी-बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, जिनके शेयर देशभर से बड़ी संख्या में लोगों के पास हैं। कुछ नामी कंपनियों में तो शेयर धारकों की संख्या लगभग 30 लाख तक है। ऐसे मामलों में, ऐसी बैठक बुलाना लगभग असंभव है जिसमें शेयर-धारिता के कुल मूल्य का तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भाग ले सकें। विचार व्यक्त किया गया यूरो कॉट्सपिन लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 391 (2) के तहत विचार किया गया तीन-चौथाई बहुमत क्रेडिट या शेयरों के कुल

[5] 2002 (109) कंपनी मामले 891

मूल्य का है, जो सही नहीं है। हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, कंपनी की तरजीही शेयर-होल्डिंग का कुल मूल्य रु। 8,45,200 जबकि बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले शेयरधारकों द्वारा दर्शाया गया मूल्य केवल रु. 6,42,700. हालाँकि, जिन लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, उन्होंने रुपये के मूल्य का प्रतिनिधित्व किया। 4,42,700 शेयरधारक के रूप में जो उपस्थित थे, उन्होंने वोट नहीं दिया। अधिनियम की धारा 391 (2) के तहत संकल्पना को अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया माना गया था। माना कि रु. 4,42,700 रुपये के तीन-चौथाई से काफी कम है 8,45,200, तरजीही शेयरों का कुल मूल्य है।

(9) 2003 के सीपी 138 में उपस्थित श्री अमित सिंह ने श्री दीवान द्वारा दिए गए तर्कों को दोहराया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हमारा ध्यान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 की ओर आकर्षित किया जो संविधान में संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 के खंड (2) में संशोधन विधेयक को "प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है"। उन्होंने आगे संविधान के अनुच्छेद 169 का उल्लेख किया, जिसमें राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने या बनाने के प्रयोजनों के लिए समान बहुमत निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में अभिव्यक्ति "वर्तमान और मतदान" का दायरा और अर्थ **डी. जयारमन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य**[6] मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। 13 मई, 1986 को विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधान सभा में एक सरकारी संकल्प पेश किया गया, जो अगले ही दिन यानी 14 मई, 1986 को चर्चा के लिए आया। उस दिन सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या 222 थी। हालाँकि , मतदान होने से पहले, कांग्रेस-आई और अकेले जी.के.एन.सी. के 60 सदस्य। सदस्य सदन से हट गये. प्रस्ताव को पक्ष में 136 और विपक्ष में 25 वोटों से पारित किया गया। विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या 136 वोट "विधानसभा के उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई" का गठन करते हैं मतदान" मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि "लेख को स्पष्ट रूप से पढ़ने से, कला में मौजूद शब्द और मतदान सामने आते हैं। 169(1) का अर्थ केवल वे लोग होंगे जो शारीरिक रूप से उपस्थित थे और मतदान कर रहे थे। इसमें वे लोग शामिल नहीं होंगे जो मतदान के समय सदन से हट गए थे।" इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि धारा के प्रयोजन के लिए तीन-चौथाई बहुमत। अधिनियम की धारा 391(2) को भी उसी तरीके से लेनदारों/शेयरधारकों के मूल्य से समझा जाना चाहिए जो बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित और मतदान कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस प्रावधान की सरल भाषा को संभवतः यह मानने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है कि निर्धारित बहुमत कंपनी के कुल लेनदारों/शेयरधारकों के मूल्य का तीन-चौथाई है। उन्होंने हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून (चौथे संस्करण) में इसी आशय की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। पैरा 1531 में, विद्वान लेखक ने, कंपनी अधिनियम, 1948 की धारा 206 की उप-धारा (2) के समान प्रावधानों से निपटते हुए देखा है कि आवश्यक बहुमत संख्या में बहुमत है

[6] एआईआर 1987 मद्रास 215

जो मौजूद लोगों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करता है और बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मतदान करना।

(10) 2003 के सीपी 8 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री आर.एस. अरोड़ा वकील ने अपने सहयोगियों श्री दीवान और श्री अमित सिंह द्वारा दी गई दलीलों को अपनाया। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 78 के अनुसार, अधिनियम की धारा 391(2) के तहत एक बैठक के परिणाम की रिपोर्ट अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत की जानी है। फॉर्म 39, एक निश्चित समय सीमा के भीतर। फिर, उन्होंने यह दिखाने के लिए फॉर्म 39 का हवाला दिया कि उसमें मांगी गई जानकारी केवल उन शेयरों/क्रेडिट के मूल्य के संबंध में थी जो उपस्थित थे और मतदान कर रहे थे। शेयरों के कुल मूल्य या कंपनी के लेनदारों के कुल मूल्य के बारे में कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार, इससे पता चलता है कि अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) के तहत परिकल्पित तीन-चौथाई बहुमत बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों/शेयरधारकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शेयरों या क्रेडिट के मूल्य का है।

(11) श्री अक्षय भान, 2003 के सीपी 223 में उपस्थित हुए और श्री सुमीत गोयल, 2003 के सीपी 150 में उपस्थित हुए और अपने सहयोगियों के तर्कों को अपनाया।

(12) श्री एम.एल. विद्वान एमिकस क्यूरी सरीन ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 391(2) की भाषा और निर्माण के सुस्थापित नियमों के आधार पर, वकील द्वारा दी गई व्याख्या याचिकाकर्ताओं के लिए यह सही प्रतीत हुआ। उन्होंने बताया कि आम तौर पर बैठकों में निर्णय उन व्यक्तियों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं जो बैठक में शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं। हालाँकि, चूंकि अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) के तहत लिया जाने वाला निर्णय दूरगामी परिणाम वाला है और सभी लेनदारों/शेयरधारकों के अधिकारों को प्रभावित करता है, इसलिए एक दूसरा सुरक्षा प्रदान किया गया है। दूसरे शब्दों में, प्रस्ताव को न केवल उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, बल्कि इसके अतिरिक्त ऐसे बहुमत को उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयरों/क्रेडिट के मूल्य का तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व करना होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153 की उप-धारा (2) के संबंधित प्रावधान में (जिसे इस निर्णय के पहले भाग में पहले ही पुन: प्रस्तुत किया जा चुका है), मूल्य में तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता थी शेयरधारकों/लेनदारों के मूल्य के संबंध में देखा जाना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित थे। यह आवश्यक नहीं था कि ऐसा व्यक्ति भी मतदान में भाग लेता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कंपनी लॉ कमेटी की रिपोर्ट, 1952 के अनुसार, यह सिफारिश की गई थी कि "वर्तमान" और "दोनों में से कोई एक" शब्दों के बीच "और वोटिंग" शब्द जोड़ा जाए। इस संशोधन का उद्देश्य इस प्रकार समझाया गया था कि "यह सुनिश्चित करना कि समझौतों और व्यवस्थाओं के संबंध में निर्णय कक्षा की बैठकों में उपस्थित और मतदान करने वाले तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएं"। इसी पृष्ठभूमि में अधिनियम की धारा 391(2) के प्रावधान लागू किये गये थे। यदि इस प्रावधान की व्याख्या यह की जाए कि बहुमत को शेयरों/क्रेडिट के कुल मूल्य का तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो, "वर्तमान और मतदान" शब्द बेमानी हो

जाएंगे, जो निर्माण के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आगे बताया कि अधिनियम में ऋणदाताओं/शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक लेनदार/शेयरधारक को व्यवस्था की एक प्रति के साथ 21 दिन का नोटिस दिया जाना है। केंद्र सरकार को भी नोटिस देना जरूरी है. हालाँकि, यदि पर्याप्त सूचना के बावजूद, कोई लेनदार/शेयरधारक बैठक में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनता है, तो उसकी निष्क्रियता संभवतः कंपनी की निर्णय लेने की प्रक्रिया को रोक नहीं सकती है। उनके अनुसार, यदि अपेक्षित बहुमत से कोई निर्णय आ जाने के बाद भी कंपनी न्यायालय इसे ऋणदाताओं/शेयरधारकों के हित के विरुद्ध पाता है, तब भी वह समझौते या व्यवस्था को मंजूरी नहीं दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक कॉर्पोरेट जगत में ऐसी कंपनियां हैं जिनमें शेयरधारकों की संख्या चलती है आईएसी में और ऐसे शेयरधारक देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। ऐसी कंपनियों को अधिनियम की धारा 391(2) के तहत अपने शेयरों के कुल मूल्य के तीन-चौथाई बहुमत का अनुमोदन प्राप्त करना लगभग असंभव है। ऐसी व्याख्या प्रावधान को अव्यवहारिक बना देगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में गहन अध्ययन के बावजूद, उन्हें अंग्रेजी कानून या भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत एक भी मामला नहीं मिला, **यूरो कॉलपिन लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले में व्यक्त दृष्टिकोण के समान ही उन्होंने यह भी कहा।).

(13) विद्वान वकील को सुनने और पुराने अधिनियम, यानी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1948 के संबंधित प्रावधानों और अंग्रेजी कानून के तहत प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद, हमारा विचार है कि धारा 391(2) के प्रयोजनों के लिए अधिनियम के अनुसार, तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता को बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शेयरों/क्रेडिट के मूल्य के संबंध में देखा जाना चाहिए, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा। इस प्रावधान की यह व्याख्या नहीं की जा सकती कि तीन-चौथाई बहुमत कंपनी के लेनदारों/शेयरधारकों के कुल मूल्य का होना चाहिए। यह सही ढंग से इंगित किया गया है कि बाद का दृष्टिकोण अपनाने से "वर्तमान और मतदान" शब्द निरर्थक हो जाएंगे, जो निर्माण के सुस्थापित नियमों के विपरीत होगा। यदि इरादा कुल मूल्य का तीन-चौथाई बहुमत रखने का था, तो प्रावधान तदनुसार लिखे गए होंगे। हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 391 (2) की भाषा पूरी तरह से स्पष्ट है और इस प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिस बहुमत से किसी समझौते या व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, उसे लेनदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। लेनदार/शेयरधारक जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं और कंपनी के शेयरधारकों या लेनदारों के कुल मूल्य का नहीं है।

(14) हम संविधान के अनुच्छेद 169 (1) के संदर्भ में **सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य**[7], (7) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उपयोगी उल्लेख कर सकते हैं: -

"169. राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण।- (एल) अनुच्छेद 168 में किसी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने या ऐसे राज्य में ऐसी परिषद के निर्माण का प्रावधान कर सकती है।

[7] एआईआर 1965 एस.सी. 845

ऐसी कोई परिषद नहीं है, यदि राज्य की विधान सभा विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करती है।''

शीर्ष न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान में "उपस्थित और मतदान" शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझाया: -

"इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कला, 568 की व्यापक योजना यह है कि यदि संसद संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जो प्रावधान में शामिल नहीं है, तो लेख के मुख्य भाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रश्न में संशोधन करने के उद्देश्य से पेश किए गए विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह आवश्यकता बताती है कि संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों से पर्याप्त समर्थन मिलना चाहिए। इसीलिए इस संबंध में दोहरी आवश्यकता निर्धारित की गई है। जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, विधेयक पारित होने के बाद, उसे राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाना है और जब वह अपनी सहमति दे देंगे, तो संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। संविधान के संशोधन के संबंध में यही स्थिति है जिसका प्रावधान लागू नहीं होता है।''

(15) अधिनियम की धारा 391 (2) भी अधिनियमित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी समझौते या व्यवस्था को लेनदारों/शेयरधारकों से पर्याप्त समर्थन मिलना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए दोहरी आवश्यकता निर्धारित की गई है। सबसे पहले, इसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त, ऐसे बहुमत को उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों/शेयरधारकों के तीन-चौथाई मूल्य का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों या क्रेडिट के नाममात्र मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, हालांकि बहुमत में हो सकते हैं, कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं जो उन व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिनके पास पर्याप्त शेयर-होल्डिंग या क्रेडिट है, लेकिन संख्या में अल्पसंख्यक हैं। इसके विपरीत, यह बड़ी शेयरधारिता रखने वाले या पर्याप्त क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ छोटे लेनदारों/शेयरधारकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है।

(16) **शिव शक्ति कूप में हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम स्वराज डेवलपर्स और अन्य**[8], निर्माण के नियमों से निपटते समय, शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार देखा: -

"19. यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालत किसी ऐसे वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकती है जो स्पष्ट और स्पष्ट हो। क़ानून विधायिका का एक आदेश है। किसी क़ानून में प्रयुक्त भाषा विधायी मंशा का निर्धारक कारक है। शब्द और वाक्यांश ऐसे प्रतीक हैं जो सन्दर्भों के प्रति मानसिक सन्दर्भों को उत्तेजित करते हैं। किसी क़ानून की व्याख्या करने का उद्देश्य इसे लागू करने वाली विधायिका की मंशा का पता लगाना है। (**इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम प्रिंस वॉटरहाउस** देखें) विधायिका का इरादा मुख्य रूप से इस्तेमाल की

[8] (2003) 6 एस.सी.सी. 659

गई भाषा से पता लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि जो कहा गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और जो नहीं कहा गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, जिस निर्माण के लिए शब्दों के समर्थन, जोड़ या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों को अर्थहीन मानकर अस्वीकार कर दिया जाता है, उससे बचना होगा। जैसा कि **क्रॉफर्ड बनाम स्पूनर** में देखा गया है, अदालतें विधायिका को किसी अधिनियम की दोषपूर्ण रूपरेखा तैयार करने में सहायता नहीं कर सकती हैं, हम जोड़ या सुधार नहीं कर सकते हैं, और निर्माण द्वारा! जो कमियां वहां रह गई हैं उन्हें पूरा करें। (गु**जरात राज्य बनाम दिलीपभाई नाथजीहाई पटेल** देखें।) किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ना निर्माण के सभी नियमों के विपरीत है जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो। (स्टॉक बनाम फ्रैंक जोन्स (टिप्टन) लिमिटेड देखें) व्याख्या के नियम अदालतों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक कि प्रावधान अर्थहीन या संदिग्ध अर्थ वाला न हो। अदालतें संसद के अधिनियम में शब्दों को पढ़ने की हकदार नहीं हैं, जब तक कि इसके लिए स्पष्ट कारण अधिनियम के चारों कोनों के भीतर नहीं पाया जाता है, (**विकर्स संस और मैक्सिम लिमिटेड बनाम इवांस** में लॉर्ड लोरबर्न, आई.सी., **जुम्मा मस्जिद बनाम कोडिमनियांद्र देवैया** में उद्धृत))

20. सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि सवाल यह है कि क्या कहा गया है। "क़ानून को यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।" जज लर्नड हैण्ड ने कहा, "लेकिन शब्दों को केवल कुछ, उनके पीछे छिपे उद्देश्यों की कल्पना से समझा जाना चाहिए" ।

(**लेनिघ वैली कोल कंपनी बनाम यांसावेज** देखें।) **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वेडेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा** मामले में इस दृश्य को दोबारा दोहराया गया था।''

(17) इसी तरह, **बबुआ राम और अन्य बनाम यूपी राज्य और दूसरा**[9], एक प्रावधान की व्याख्या का उद्देश्य पैरा-23 में वर्णित किया गया है, जैसा कि: -

"23. व्याख्या का उद्देश्य! इसलिए, विधायिका के इरादों को सुनिश्चित करना और इसे प्रभावी बनाना है। यदि क़ानून अस्पष्ट है या उसका अर्थ अनिश्चित है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या का सहारा लिया जाता है कि क़ानून में शब्दों से विधायिका का क्या मतलब है, हालांकि वे विधायी हित को स्पष्ट और पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि क़ानून स्पष्ट, निश्चित और अस्पष्टता से मुक्त है, तो इसका केवल पढ़ना ही पर्याप्त है और इसकी व्याख्या कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। विधायी इरादे की खोज में, अदालतें विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रही हैं बल्कि कुछ कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए सामान्य ज्ञान के नियमों को लागू कर रही हैं।"

[9] (1995) 2 एस.सी.सी. 689

उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि अधिनियम की धारा 391(2) की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है। इस प्रावधान में प्रयुक्त शब्द और वाक्यांश स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता शेयरधारकों या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शेयरों/क्रेडिट के मूल्य से संबंधित है, न कि कंपनी के शेयरों/क्रेडिट के कुल मूल्य से। अंग्रेजी कानून के तहत समान प्रावधानों की व्याख्या करते समय अदालतों द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया गया है। हमारे अनुसार, यह एकमात्र व्याख्या है जिसे अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) में "उपस्थित और मतदान" शब्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यूरो कॉटस्पिन लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में व्यक्त किया गया विपरीत दृष्टिकोण, हमारे विचार में, सही नहीं है। इस तरह के निष्कर्ष पर केवल तभी पहुंचा जा सकता है जब शब्द "मूल्य में तीन-चौथाई" को "कुल मूल्य में तीन-चौथाई" के रूप में पढ़ा जाए और '''वर्तमान और मतदान'' शब्दों को नजरअंदाज कर दिया जाए। ऐसा दृष्टिकोण अच्छी तरह से स्थापित नियमों के खिलाफ है निर्माण का, क्योंकि इसमें प्रावधान में प्रयुक्त नहीं किए गए शब्द "कुल" का आयात और साथ ही "वर्तमान और मतदान" शब्दों को निरर्थक मानकर अस्वीकार करना शामिल है।

(18) तदनुसार, संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है।

(19) इन याचिकाओं को अब हमारे निष्कर्षों के आलोक में निपटान के लिए कंपनी न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी

Hardik Sachdeva

Trainee Judicial Officer

Place of Posting: Bhiwani